



सागर, मंगलवार 1 अप्रैल 2025

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

सोनिया के उठाये मुद्दों पर ध्यान दे सरकार!

क्रांतिकारी पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सदस्य सोनिया गांधी ने एक लेख में केन्द्र सरकार की उसकी शिक्षा नीति को लेकर जमकर घेराबन्दी की है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के मक्सद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जनता पर थोप रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंडू में प्रकाशित होने के बाद जमकर चर्चा में आये इस लेख में सोनिया गांधी ने इस बात की अलौचना की है कि भाजपा सरकार ने 'सी 3' (कंट्रीकरण-सेंटलाइजेशन, छवा/वसायीकरण-कर्मशाला-उन्नीसलिङ्ग) के अपने एंजेंडे को आगे बढ़ाने का साधन नई शिक्षा नीति (एनईपी) को बनाया है। इस लेख में वैसे तो कांग्रेस नेत्री ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं परन्तु इसका मुख्य फोकस शिक्षा प्रणाली के बोर्ड के आयाम हैं जो देश के लिये विनाशकारी साबित होंगे। उन्होंने एनईपी में अनेक खामियां गिनाते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का पूरा करने के लिये बनाई गई है।

शिक्षा किसी भी समाज के विकास की बुनियाद होती है। सोनिया के इस लेख में एनईपी से उत्पन्न होने वाले खतरे तथा उनकी चिंताएं साफ झलकती हैं जो इस बात का भी आधास करती हैं कि इस शिक्षा प्रणाली की राह पर चलकर बनने वाला समाज व देश कैसा होगा। इस लेख में सरकार की शिक्षा के प्रति बरती जाने वाली तीव्रता और उनके जो हालात होंगे, उसकी ओर साफ इशारा सोनिया गांधी के लेख में है।

मुख्यतः जिस 'सी 3' का उहोंने अपने लेख में जिक्र किया है, उसके पहले 'सी' यानी केन्द्रीकरण के बारे में बात की जाये तो यह तो साफ है कि यह सरकार समाज के हर सांसाधन व अवसरों पर एकाधिकार कर रही है। इनमें शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा का निष्कर्ष है जो हर उस नागरिक को परेशान करने के लिये काफी होना चाहिये जो मुल्क के बहतरी की सोचता हो। नई शिक्षा प्रणाली के नाम पर बच्चों को जिस प्रकार से ढाला जायेगा और उनके जो हालात होंगे, उसकी ओर साफ इशारा सोनिया गांधी के लेख में है।

मुख्यतः जिस 'सी 3' का उहोंने अपने लेख में जिक्र किया है, उसके पहले 'सी' यानी केन्द्रीकरण के बारे में बात की जाये तो यह तो साफ है कि यह सरकार समाज के हर सांसाधन व अवसरों पर एकाधिकार कर रही है। इनमें शिक्षा व्यवस्था भी है। लेख में कहा गया है कि वैसे तो शिक्षा समर्थक सूची में शामिल है, यानी वह केन्द्र व राज्य दोनों का ही विषय है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मसले पर केन्द्र सरकार न तो राज्यों से चर्चा करती है और न ही वह विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा लेती है। वह इस मामले में अपनी मर्जी तो थोपती है बल्कि उसका रवैया 'धमकी भरा' भी होता है। उहोंने इस मामले में तमिलनाडु के साथ केन्द्र द्वारा राज्यों पर हिन्दी को थोपने की कोशिशों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

दूसरे 'सी' यानी व्यवसायीकरण की बात करें तो यह पहले ही साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार शिक्षा को इतनी महंगी कर देने पर आमादा है कि वह सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो जाये। इसके कारण देश में वर्गभेद और भी बढ़ेगा। थोड़े से लोग ही इस शिक्षा को पाने का खर्च वह का संकेंगे जबकि अधिसंख्य जनता स्कूल-कॉलेजों का खर्च वहन नहीं कर सकते। शासकीय व स्पस्ती शिक्षा की बजाय निजी व महंगी शिक्षा के प्रति सरकार का रुझान साफ दिखाई देता है।

सोनिया गांधी द्वारा उल्लेखित तीसरा 'सी' इस फार्मूले का सबसे खतरनाक पक्ष है- शिक्षा का साप्रदायिकरण। इस शिक्षा पद्धति में आधुनिकता का अभाव है। उहोंने ध्यान दिलाया है कि पाठ्यक्रम से महात्मा गांधी और मुगलकालीन इतिहास को हटाया जा रहा है जो कि बहुत गम्भीर है। इतिहास में हुई घटनाएं किसी को पसंद आयें, वे हो चुकी हैं; लेकिन भाजपा अपनी सरकार के जरिये उहोंने इसलाये मिटाना चाहती है ताकि उसका हिन्दूत्व का एंजेंडा पूरा हो। यह बच्चों में आधुनिक, तटस्थ व वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शिक्षा की जगह पर पिछड़ी सोच तथा पूर्वग्रहों वाली प्रणाली लागू करने का प्रयास है। इसका मक्सद अल्पसंख्यकों के खिलाफ नकरत तथा हिंसा को बढ़ावा देना है जो कि भाजपा का अगले कई वर्षों तक का वोट बैंक बनायेगा। राजनीतिक स्तर पर किया गया ध्रुवीकरण, जिसके बल पर भाजपा ने सत्ता हासिल की है- उसे बनाये रखना भी इसी प्रणाली के जरिये होगा।

दरअसल भाजपा सरकार देश को उसी मध्य युग में ले जाना चाहती है जहां समाज का आधार मनुवादी व्यवस्था हो। इसमें शिक्षा उन थोड़े से लोगों के लिये उपलब्ध होती जो विशेषधिकार प्राप्त हों। देश की बहुसंख्य आबादी निरक्षर या अल्प विशिष्ट रहे जिसे अपने अधिकारों के प्रति न तो जानकारी हो, न ही वह अपने विकास की बात करे। संघ का पूंजीवाद में विश्वास है। कुछ लोगों के हाथों में सारी आर्थिकताकर सिमट जाने पर उनके लिये सस्ता मानव श्रम जुटाने की जिम्मेदारी इसी शिक्षा प्रणाली की होगी। इतना ही नहीं, इसी शिक्षा प्रणाली में ऐसे नागरिकों की पौधे तैयार हो रही है जो भाजपा के निर्देश पर समाज में हिंसा व ध्यान फैलाने का काम अगले कई बारों तक करती रहेगी। इसलिये इसका विरोध जुरूरी है। सोनिया जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नागरिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। हथर्थमिता छोड़कर सरकार इस ओर ध्यान दे।

पृष्ठ

'क्रिम बुद्धिमता' (एआई) दुनिया भर की दशा और दिवाली देश के लिये लेकर एक अलग दुनिया के दावे किए जा रहे हैं। 'एआई' के चौंकाने वाले आविकारों की जानकारी और उनके उपयोग के साथ इसके खतरों के कहानी-किस्से भी मीडिया के माध्यम से दुनिया को सुनेने मिल रहे हैं। ऐसे में पत्रकारिता इससे क्षेत्रों पर आधारित है। 'एआई' का चमकाकर और परामर्श देखकर लगता है कि वह प्रौद्योगिकी ही तो वाला देखे। क्या वास्तव में पत्रकारिता के साथ ऐसा होगा? इसे लेकर जिन प्रयोग, चिंतन, बहस और चर्चा दुनिया के उत्तरी गोलांधर के विकसित करे जाने वाले देशों में शायद नहीं है।

'ग्लोबल साउथ' के पत्रकारों में 'एआई' को लेकर असमंजस है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़े जीवनमें और दायित्व, मीडिया प्रबन्धन में नीतिगत उदासीनता, महंगे उपकरण, प्रशिक्षण का अभाव जैसे कारण 'एआई' पत्रकारिता की राह में बाधक है। तकनीकी विकास के इस दौर में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनेक वाले वर्षों में 'एआई' की दिखा बदलती है या वह नहीं और क्या 'ग्लोबल साउथ' का विकासील देशों में पत्रकारिता के लिये एक संसाधन होगा।

इस तकनीक को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता तो बहुत है, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में अधिकारों बहस या बातचीत विकसित देशों तक ही कीटित है। ऐसे व्यापक, लेकिन असमान है। सर्वेक्षण में 'एआई' प्रौद्योगिकी के लिए 'सर्कर' 'आशावाद' पाया गया, एक ऐसी भावना जो शायद इस तथ्य को झुलाती है कि वैश्वक-दक्षिण में 'एआई' की अपनाना महत्वपूर्ण है। 10 में से आठ से अधिक (81.7फीसदी) पत्रकार अपने काम में 'एआई' के उपकरणों का उपयोग करते हैं। 13फीसदी पत्रकारों ने बताया कि उनके न्यूज़रूम में 'एआई' नीति है, हालांकि इसे अपनाने में अन्य बाधाओं की भी सामना करना पड़ता है। कई पत्रकारों ने 'एआई' उपकरणों तक सीमित पहुंच, उच्च लागत और प्रशिक्षण की साथ-साथ मार्गदर्शन की रूप में आपनाने की दिखाए गए बदलते हैं।

पत्रकार मुख्य रूप से कटेंट का प्रारूप तैयार करने और संपादन, ट्राईक्रिटिंग, तथ्यों की जांच और सोध प्रयोग के लिये एक अप्रैक्टिक अंग्रेजी के लिए 'जनरेटर' एआई' का उपयोग करते हैं। 'वैटर्जीपीटी', 'ग्रामली', 'ओटर' और 'कैनेट' जैसे उपकरण कई पत्रकारों के लिए आवश्यक हैं।

'थार्मसन रंगवर्स फारंडेशन' (टीआरएफ) की एक रिपोर्ट, जो दुनिया के 70 से अधिक देशों के 200

से अधिक पत्रकारों के सर्वेक्षण के अधिकारों के लिये आधारित है, साथ ही एआई के आधारित है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है।

सर्वेक्षण को लेकर देशों के अधिकारों के लिये आधारित है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है।

सर्वेक्षण को लेकर देशों के अधिकारों के लिये आधारित है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश लगता है।

सर्वेक्षण को लेकर देशों के अधिकारों के लिये आधारित है। इसे लेकर अध्ययनकर्ता डिम्पियर रेडिकल पत्रकारिता से बताते हैं कि वह एआई की जानकारी और आशावाद का प्रकाश ल

पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग लगने से झुलसी, घर में आरती करते समय हुआ हादसा



उदयपुर, एजेंसी। कांगड़े की बरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास को राजस्थान के उदयपुर शहर में अपने घर में आरती के दौरान हादसे का शिकाया हो गई। 79 वर्षीय गिरिजा व्यास को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया।

बताया जाता है कि गिरिजा आरती के रही थी। उन्होंने जलते दीपक से उनके दृष्टियों में आग लग गई। परिवार के सरस्य उन्हें अस्पताल ले गए। घर में ही काम कर रहे लोगों ने उन्हें संभाला। गिरिजा व्यास की बहू दिलासा शर्मा ने बाबाया कि उनकी सास गौणपूरा पाज कर रही थी। सीधी दौरान नीचे जल रहे दीपक से चुप्पी ने आग पढ़ ली। इससे बहू झुलस गई। वे राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री के अलावा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरिजा व्यास के झुलसने पर चिनिया जारी है। इस दौरान उन्होंने एकम पर पोस्ट किया, पूर्व के निजी व्यास के खुलसकर घायल होने का समाचार काफी चिंताजनक है। वे ईश्वर से उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्राश्ना करता हूं।

प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री परिवहन सेवा, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद होगा योजना का कियाज्वर्यन

सुदूर क्षेत्रों में आसान होगा आवागमन

- ▶ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्यालियर, ऊजैन, सागर और रीवा में क्षेत्रीय कंपनियां गठित होंगी
- ▶ जिला स्तर पर गठित की जाएंगी यात्री परिवहन समितियां



भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण शहरी और इंटरसिटी परिवहन व्यवस्था को सुदूर होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। योजना का प्रारंभ तैयार कर लिया गया है। सबके साथ विस्तृत विचार-विमर्श, सुझाव एवं सहमति के बाद शीर्षी ही इस योजना प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मंत्री-परिषद की बैठक में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समृद्ध भवन में नवीन परिवहन सेवा (मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा) के संबंध में प्राथमिक चर्चा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में परिवहन सेवाओं की ओर बेहतर

प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सुगम प्रयास की गयी। पैंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री कैलश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बैठक में वर्तुलीती सहभागिता की। समूल में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा (मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा) के संबंध में प्राथमिक चर्चा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विशेषकर

ग्वालियर, ऊजैन, सागर एवं रीवा) में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी गठित की जाएंगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति गठित भी की जायेंगी। यह सभी बॉडीज यात्री परिवहन को बेहतर बनाने, यात्री किराया तय करने, रुट चार्ट तैयार करने में समर्वय और यात्रियों को योजना का अधिकात्म लाभ दिलाने के लिए अनुरोध एवं मार्गिनिंग करेगी।

बताया गया कि सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की आय अर्जन के स्रोत नियमांकित है। इसी योजना में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। नवीन योजना में सरकार अनुरोधित बसों को प्राथमिकता से परिवहन देगी। इन बसों पर प्रभावी नियन्त्रण सरकार का ही होगा। नवीन योजना में यात्रियों को इसका अधिकात्म लाभ मिल सके।

सचिव परिवहन मनीष सिंह ने नवीन परिवहन सेवा योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई परिवहन योजना में प्रदेश में यात्री बसों के संचालन की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग सरकार की विभागीय विकास एवं प्रशासन सेवा सेवाकारी की विभागीय विकास एवं प्रशासन सेवा

राज्यपाल ने आचार्य बालकृष्णन से सिक्कल सेल के संबंध में की चर्चा



भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल मंत्रुमाई पटेल ने आयुर्वेद में सिक्कल सेल उपचार अनुमति ग्रहण की अपेक्षा द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा तृप्त की गयी है।

राज्यपाल द्वारा परंतु योगपीठ द्वारा के संसाधक से अधिकारी द्वारा

